न्यायालय में चला गया और 20 फरवरी 2018 को उच्चतम न्यायालय ने कहा कि NRC का काम नहीं रूकेगा।

कांग्रेस सरकार भी बता चुकी है घुसपैठियों की बड़ी संख्या के बारे में

पिछले साल नवंबर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में बताया था कि असम में लगभग दो करोड़ अवैध बांग्लादेशी हैं। यही नहीं आज की सरकार पर आरोप लगा रही कांग्रेस यह भूल रही है कि यूपीए सरकार ने 2004 में राज्य में 1.2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी होने का अनुमान जताया था।NRC के तहत 24 मार्च, 1971 के पहले राज्य में बसे लोगों को मूल निवासी माना गया है। खुद को मूल निवासी साबित करने के लए लोगों को उस तिथि से पहले की किसी वोटर लिस्ट में नाम होने के प्रमाण या अपने पूर्वजों से संबंध के दस्तावेज पेश करने होंगे।

चुनाव में भाजपा ने किया था घुसपैठ रोकथाम का वादा

भाजपा ने तो असम विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य में अवैध आव्रजन को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाते हुए अपने दृष्टिपत्र में यह सुनिश्चित करने का वादा किया था कि भारत-बांग्लादेश सीमा सील की जाएगी। असम विधानसभा चुनाव के लिए दृष्टिपत्र जारी करते हुए भाजपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री तरूण गोगोई पर घुसपैठ को बढ़ावा देने तथा राज्य की जनसांख्यिकी नष्ट करने का आरोप भी लगाया था। तब केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने गोगोई सरकार पर आरोप लगाया था कि ''कांग्रेस ने घुसपैठ को बढ़ावा दे कर राज्य की जनसांख्यिकी को बदलने तथा नष्ट करने की कोशिश की। कांग्रेस कई दशकों से ऐसा कर रही है और उसने कोई कार्रवाई नहीं की।'' भाजपा ने अपने दृष्टिपत्र में यह भी वादा किया था कि घुसपैठियों को रोजगार देने वाले उद्योगों, कारोबारियों, छोटे एवं मध्यम उद्यमों तथा अन्य एजेंसियों के साथ कठोरता से निपटने के लिए भी कानून बनाया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास कर लीजिये

चलिए मान लेते हैं विपक्ष को सरकार पर विश्वास नहीं लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास करना चाहिए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के एक बयान को लेकर असम सरकार को फटकार लगाई थी। सोनोवाल ने बयान दिया था कि NRC का मसौदा इस साल के आखिर तक प्रकाशित कर दिया जाएगा। अदालत ने कहा था कि जब उसके द्वारा बनाई गई एक समिति इस मसौदे की प्रकाशन प्रक्रिया की निगरानी कर रही है तो कोई और इस तरह के बयान नहीं दे सकता। शीर्ष अदालत का यह भी कहना था कि अगर ऐसा करना ही है तो फिर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाली ही इसकी निगरानी कर लें। विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री NRC के मामले में बयान भी नहीं दे सकते थे तो इसे अपडेट करने की प्रक्रिया में छेड़छाड़ की तो गुंजाइश ही नहीं बचती।

उच्चतम न्यायालय ने कहा भी है कि असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में जिन लोगों के नाम नहीं हैं उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए क्योंकि अभी यह सिर्फ मसौदा ही है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से कहा है कि असम के एनआरसी के संबंध में दावों और आपत्तियों को देखने के लिए वह मानक संचालन प्रक्रिया बनाए। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को 16 अगस्त से पहले मानक संचालन प्रक्रिया मंजूरी के लिए पेश करने का निर्देश देते हुये कहा है कि सूची से बाहर रखे गये लोगों को अपने दावे पेश करने के लिए पूरा मौका देना चाहिए।

अमेरिका नाराज होता है तो हो, भारत को ईरान से संबंध प्रगाढ़ रखने चाहिए

यदि यह मान भी लिया जाए कि अमेरिका ने भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक किसी 'देवी उल्का-पात' के कारण टाली, तो भी राष्ट्रसंघ में अमेरिकी राजदूत निकी हैले की दिल्ली यात्रा में भारत से अमेरिकी परेशानियां जाहिर हो गयीं। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत ईरान के साथ संबंध रखे.. और वह रूस से 4.5 अरब डालर की लागत से खरीदे जा रहे विमान भेदी प्रक्षेपास्त्र रक्षा-व्यवस्था-टायम्फ-5 के खिलाफ भारत पर प्रतिबंध लगाने का संकेत दे चुका है। ये प्रतिबंध अमेरिका द्वारा पारित 'अमेरिकी के विरोधी-प्रतिस्पर्धियों के प्रतिरोध हुते प्रतिबंध कानून' (सीएएटीएसए काट्सा) के अंतर्गत लगाए जाएंगे।

निकी हैले ने दिल्ली में स्पष्ट कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्ट कहा है कि भारत ईरान से अपने संबंधों पर पुनर्विचार करें। इसका कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ईरान के प्रति आक्रामक नीति है, जिस कारण उन्होंने 2015 में राष्ट्रपति ओबामा द्वारा पांच अन्य देशों- चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान से परमाणु समझौता किया था, जिसके अंतर्गत ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करेगा तथा बारह वर्ष से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंध क्रमशः हटा लिए जाएंगे। ट्रम्प ने अपने चुनाव में वचन दिया था कि वे इस समझौते को रद्द करेंगे और पांच देशों की असहमति के बावजूद उन्होंने ऐसा कर भी दिया जिसके कारण नवम्बर 2018 से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लागू हो जाएंगे।

भारत ने दृढ़तापूर्वक ईरान से अपने परम्परागत सभ्यतामूलक संबंधों को दोहराया। पर सम्पूर्ण विश्व का आर्थिक-व्यवहार डालर केंद्रित है। यदि अमेरिका ईरान से हर आर्थिक संबंध को रोकता है तो क्या भारत के लिए अपना आर्थिक व्यवहार जारी रखना संभव होगा?

सामरिक दृष्टि से ईरान भारत का महत्वपूर्ण सामरिक देश है। वह भारत को तेल आपूर्ति करने वाला तीसरा बड़ा देश है- 2 करोड़ 72 लाख टन तेल गत वर्ष मिला। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के खतरे के सामने मुंबई व गुजरात को 7200 किलोमीटर लम्बे उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जोड़ने का मार्ग ईरान के चाबहार, बंदर अब्बास होते हुए

नरेंद्र मोदी इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा (जुलाई 2017) से पहले मई 2016 में ईरान की यात्रा पर गए थे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की गत 15 वर्षों में यह पहली यात्रा ईरान यात्रा थी जहां उन्होंने अफगानी राष्ट्रपति राष्ट्रपति की उपस्थिति में चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पर भारत साढ़े आठ करोड़ अमेरिकी डालर खर्च कर चुका है और ईरान से अफगान सीमा पर रेल मार्ग भी बना रहा है। कई मुद्दों पर मत भिन्नता भी है- जैसे कश्मीर। पर आज सामरिक रिश्ते उन सब पर भारी पड़ते ही हैं।

अजरबैजान तथा रूस के सेंट पीटर्स बर्ग तक पहुंचता है जो भारत के लिए इतना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। ईरान शिया देश है और भारत में शियाओं की जनसंख्या ईरान के बाद सबसे ज्यादा है। (प्रायः 3.5 से 4 करोड़)। भारत-ईरान प्राचीन संबंध एक अलग पक्ष है। भारतीय भाषाओं पर फारसी प्रभाव प्रचुर मात्रा में है बल्कि एक प्रदेश पंजाब का नाम भी फारसी से आया कहा जाता है (पंच+आब)। राजनयिक धर्म का एक ही उद्देश्य होता है- अपने देश का हित। भारत अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए अपने हितों से समझौता क्यों करे और क्यों अपनी स्वतंत्र नीति अमेरिकी दबाव में बदले?

नरेंद्र मोदी इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा (जुलाई 2017) से पहले मई 2016 में ईरान की यात्रा पर गए थे। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की गत 15 वर्षों में यह पहली यात्रा ईरान यात्रा थी जहां उन्होंने अफगानी राष्ट्रपति की उपस्थिति में चाबहार बंदरगाह के विकास हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस पर भारत साढ़े आठ करोड़ अमेरिकी डालर खर्च कर चुका है और ईरान से अफगान सीमा पर रेल मार्ग भी बना रहा है। कई मुद्दों पर मत भिन्नता भी है- जैसे कश्मीर। पर आज सामरिक रिश्ते उन सब पर भारी पड़ते ही हैं।

ऐसे ही प्रगाढ़ और विश्वसनीय संबंध रूस के साथ हैं। आज भी रूस भारत को सैन्य सामग्री की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। 68 प्रतिशत भारतीय सैन्य आवश्यकताएं रूस पूरी करता है। अमेरिका 14 प्रतिशत व इजरायल 7.2 प्रतिशत का क्रम बहुत बाद में आता है। क्या भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की धमकी के कारण रूस से अपने दशकों पुराने रिश्तों में खटास आने देगा?

सत्य यह है कि भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संवाद के 50 से ज्यादा मंच हैं। आपसी व्यापार 115 अरब डालर का है। (चीन के साथ भारत का व्यापार दूसरे क्रम पर है 84.44 अरब डालर)। भाषा, लोकतंत्र और पुराने संबंधों की साझेदारी के बावजूद अमेरिका कभी रूस की तरह भारत का भरोसेमंद मित्र नहीं रहा। फिर भी वर्तमान भू राजनीतिक समीकरणों में भारत-अमेरिका-जापान-आस्ट्रेलिया का सामरिक चीन के समक्ष एक अविजेय ध्रुव बनाता है।इसलिए ट्रम्प की सनक भरी उतार-चढ़ाव वाली विदेश नीति के बावजूद भारत को एक संवेदनशील शक्ति संतुलन बनाने की जरूरत होगी।

निकी हैले ने दिल्ली में कहा कि ईरान अगला उत्तरी कोरिया होगा। यह अमेरिकी दृष्टि है। भारत की दृष्टि में अगला उत्तरी कोरिया पाकिस्तान है, जो प्रतिदिन भारत पर आतंकवादी हमले करता है, आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चलाता है, खुले तौर पर आतंकी सरगना हाफिज सईद को राजनीति में आने देता है। अगर भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका को पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने चाहिए, जो वैश्विक आतंक का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। लेकिन निकी हैले पाकिस्तान पर महज शाब्दिक बयानबाजी का कड़ापन पर्याप्त समझती है- जिसका यथार्थ में कोई महत्व नहीं है।

भारत की विदेश नीति भारत को ही तय करनी होगी, अमेरिका को उसका कोई अधिकार नहीं। यह हमारा विषय है कि हम अपने मित्र और सहयोगी तय करें। मोदी की विदेश नीति का सफल पक्ष यह है कि इजरायल, सऊदी अरब और ईरान जैसे देशों के साथ जिनका कोई परस्पर मैत्री संबंध नहीं- बल्कि प्रबल शत्रुताएं हैं- भारत के अच्छे संबंध हैं। जो नीति भारत-हित साधे वही नीति हमारे राजनयिक संबंधों की कसौटी है। अमेरिका, अमेरिकी हितों के लिए काम करें, लेकिन अमेरिकी हितों के लिए भारत कभी अपनी विदेश नीति में बदलाव नहीं लाएगा- यह निश्चित है।

यही मोदी नीति है। ट्रम्प और निकी हैले को भारत के मित्र चुनने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाले छह महीने विदेश नीति की दृढ़ता की परीक्षा के होंगे। अमेरिका अपने सामरिक हितों के लिए विश्व के तानाशाहों, शाही परिवारों, अलोकतांत्रिक एवं अत्यंत मध्ययुगीन मानसिकता के शासकों से अच्छे संबंध बनाकर चलता है। लेकिन भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश पर आतंकी हमले करने वाले पाकिस्तान पर ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करता, जो वह ईरान पर करना चाहता है। यही उसका पाखंड है।